अल्कोहल एवं प्रोहिबिशन पर एकमात्र हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष-14, अंक-9, मई 2024

आबकारी टाइम्स

केवल सदस्यों हेतु

मक्का होगा भविष्य का विकास इंजन

यूपीडीए की उद्योग और किसान विकास की योजनाएं

हरियाणा

हरियाणा एक्साइज पॉलिसी 2024-25

सरकार को मिलेगी 150 करोड़ की अतिरिक्त आय

राजस्थान

लाईसेंस रिन्यू कराना अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश

आबकारी राजस्व मिला 13 प्रतिशत अधिक

यूपी में बिक रहे, 1700 से अधिक मदिरा के ब्रांड

देशी मदिरा की मांग में 12 प्रतिशत की हुई वृद्धि

बढ़ती मांग को देखते हुए, ब्रुअरीज ने बढ़ाया उत्पादन

शराब, शराब है चाहे वह वाइन हो अथवा बीयर

इसवाई रिस्पांसिबल ड्रिंकिंग के रेगुलराइजेशन को देती है बढ़ावा

मक्का होगा भविष्य का विकास इंजन
यूपीडीए की उद्योग और किसान विकास की योजनाएं

रजनीश अग्रवाल

यूपी डिस्टिलर्स एसोसिएशन (यूपीडीए) 1983 से डिस्टिलरी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष राज्य निकाय है, जो नीति और विनियामक मामलों पर सलाहकार की भूमिका निभाता है। नीति और विनियामक मामलों पर विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के साथ यूपीडीए उद्योग से सम्बन्धित मामलों को रखने के लिए अधिकृत संस्था है। हाल के वर्षों में यूपीडीए एक ऐसे अग्रणी उद्योग संघ के रूप में उभर कर सामने आया है जिसने एथेनॉल उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। एथेनॉल के फीडस्टॉक के रूप में उभर रहे मक्का पर कई सरकारी और निजी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के साथ एडवासं स्टेज में डिस्कशन जैसे ऐतिहासिक कदम यूपीडीए द्वारा उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नव विकसित संकर मक्का किस्मों का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन और डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन विद सॉल्यूबल्स (डीडीजीएस) में उच्च एथेनॉल रिकवरी और बेहतर प्रोटीन गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। भविष्य में 'मक्का' यूपी और भारत के आगे के विकास और महत्वाकांक्षी ई-20 ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ईएसवाई 2023-24 के एथेनॉल टेंडर में अकेले मक्का फीडस्टॉक से 30 प्रतिशत से अधिक अर्थात 198 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके लिए 5 मिलियन मीट्रिक टन मक्का की आवश्यकता है। कुछ यूपीडीए सदस्य पहले से ही जलग्रहण (कैचमेंट) क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी संगठनों से उपलब्ध सर्वोत्तम बीजों को खरीद के साथ बुवाई करा रहे हैं। वर्तमान में न केवल भारत में मक्का का उत्पादन सीमित है, बल्कि गुणवत्ता में सुधार और बदलाव की भी आवश्यकता है।

कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)/ एकीकृत कृषि मूल्य श्रृंखला विकास (पीपीपीएवीसीडी) योजना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत आसवनी के 50-100 किलोमीटर के क्षेत्रों में मक्का की खेती की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का

उत्पादन के लिए सर्वांगीण कदम उठाते हुए इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया है। यूपीडीए ने सरकारी कार्यक्रमों को अपना समर्थन देते हुए इस क्षेत्र के सभी हितधारकों अर्थात् किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), बीज निर्माता, बुवाई और कटाई मशीनरी निर्माता और ईकोसिस्टम को विकसित करने में सम्बंधित लोगों को शामिल करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप से भविष्य में मक्का उत्तर प्रदेश और भारत के विकास और महत्वाकांक्षी ई-20 ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हमें यह जानकर खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का उत्पादन के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करते हुए कई कदम उठाए हैं। यूपीडीए और सदस्य डिस्टिलरियां सरकार के उठाये कदमों का समर्थन करते हुए अपनी योजना में 150 किमी के दायरे में जल ग्रहण क्षेत्र में मक्का बुवाई को प्रोत्साहित कर रही हैं। मक्का का फसल क्षेत्रफल बढ़ाने, उच्च उपज देने वाली किस्में विकसित करने, मशीनरी के लिए विशेष प्रोत्साहन और सब्सिडी के साथ फसल विविधीकरण के लिए रोड मैप के मुताबिक कार्य किया जा रहा है। यूपी में जलग्रहण क्षेत्रों में किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही गुजरात में प्रचलित मॉडल को अपनाने पर जोर देना होगा। प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने और मक्का उत्पादकों के लिए ई-नाम जैसे ऑनलाइन बाजार को विकसित करना होगा, ताकि बेहतर मूल्य निर्धारण और किसानों तथा उद्योगों के बीच सीधा संपर्क सुनिश्चित हो सके।

मक्का विकास के लिए यूपीडीए का प्रयास राष्ट्रीय सीमाओं से आगे भी है। यूपीडीए की टीम यूएस कृषि विभाग के तहत आने वाली यूएस ग्रेन्स काउंसिल के बुलाने पर अक्टूबर 2023 में वाशिंगटन में मक्का और एथेनॉल के अध्ययन और जानकारी के लिए यात्रा पर गई थी। एथेनॉल क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में यूपीडीए और यूएस ग्रेन्स काउंसिल (यूएसजीसी) के बीच एक ग्राउंडब्रेकिंग एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। यह दोनों देशों के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिकों और उद्योग के दिग्गजों की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक दिन था। इस समझौते से भारतीय कृषि क्षेत्र और पारिस्थितिकी तंत्र में समझ बढ़ेगी, जिससे उच्च एथेनॉल के क्षेत्र में यूएसजीसी के प्रौद्योगिकियों से लाभ मिलेगा। आने वाले समय में मक्का के अधिकतम उपयोग के लिए प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफार्म आदि का लाभ किसानों को प्राप्त होगा। यूपीडीए उद्योग, राज्य और राष्ट्र की सेवा में दृढ़ विश्वास के साथ बना हुआ है और खड़ा है। -महासचिव (यूपीडीए)